

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : 5 अक्टूबर, 2007

विषय:- उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के साज-सज्जा हेतु वित्तीय वर्ष 2007-2008 में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से अतिरिक्त धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 3629/यू०एच०सी०/एडमिन-बी./उजाला/2007, दिनांक 10.8.2007 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल के साज-सज्जा हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार रु० 55,41,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 53,28,000/- (तिरपन लाख अठ्ठाईस हजार रुपये मात्र) की लागत के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2007-08 में सम्प्रति बजट में कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण तथा वर्तमान में उक्त कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न बी०एम०-15 के स्तम्भ-1 में अंकित मद में अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से बी०एम०-15 के स्तम्भ-5 में अंकित मद संख्या-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण में रु० 53,28,000/- (तिरपन लाख अठ्ठाईस हजार रुपये मात्र) की धनराशि के व्यावर्तन की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) आगणन में उल्लिखित दरें केवल आगणन गठित के लिए ही अनुमन्य हैं । कार्य कराने से पूर्व दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।
- (2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय ।
- (3) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूलस, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशाली अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।
- (4) यह भी सुनिश्चित करें कि उपर्युक्त अनुदान से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

(5) व्यय उसी मद में किया जायेगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-09-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी-00-12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-940/XXVII(5)/2007, दिनांक 3.10.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

संलग्नक- बी०एम०-15 ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

संख्या : 20-दो(2)/XXXVI(1)/2007-3-दो(2)/07-टी०सी०-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
- 3- अपर निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, नैनीताल ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 5- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 6- एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(के०पी०पाटनी)
अनु सचिव ।

डी.एम.-15
पुनर्विनियोग 2007-2008 आयोजनोत्तर

नियंत्रक अधिकारी का नाम- महालेखकार, मा०, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
प्रशासनिक विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8
2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-105-सिद्धित और शेषान्त न्यायालय-05-न्यायिक भवनों का प्रतिकर	महानगर विकास अध्यापकिक व्याय	द्वितीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (शेषान्त) धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जाती है। 2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनोत्तर-800-अन्य व्यय-00-09-उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी	पुनर्विनियोग के बाद स्वयं-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्वयं 1 में अवशेष धनराशि	अन्य विवरण
42-अन्य व्यय	6999	999	6000-क	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5378-ख	1671	क-मिलानका क कारण उपलब्ध प्रवर्तक ख-प्रशिक्षण व प्रदान एवं उपलब्धता होने के कारण ।
कुल धनराशि	6999	999	6000		5378	1671	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग में बजट में अनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त विभाग

संख्या-949-क/XXVII(5)/2007
देहरादून : दिनांक : 3 अक्टूबर, 2007

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखकार (लेखा एवं हकदारों),
उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहरानपुर रोड,
भाजग, देहरादून ।

(एन०एन०प्रसिवाल)
अपर सचिव, वित्त ।

संख्या- 20-दो(2)XXXXVI(1)2007-3-दो(2)07-टी०सी०-तद्विनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखकार, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. अपर निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भगवती, नैनीताल ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
5. वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन/एन०आई०सी०/संवर्धित सहायक/गाई बुक ।

आडा से,
(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।